eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 08, August 2025

भारत की G-20 अध्यक्षताः संकल्पना, नीतिगत सुझाव और प्रभाव

डा0 मो0 इसरार खॉ[1]
[1]असि0 प्रो0 वाणिज्य, वीरागना अवंतीबाई राजकीय महा0 अतरौली अलीगढ़

Received: 20 August 2025   Accepted & Reviewed: 25 August 2025, Published: 31 August 2025

Abstract

भारत की 2023 की जी–20 अध्यक्षता ने वैश्विक शासन व्यवस्था में भारत की भूमिका को एक नई दिशा प्रदान की। "वसुधैव कुटुम्बकम्– एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की थीम के अंतर्गत भारत ने न केवल वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया, बल्कि जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुपक्षीय संस्थागत सुधार तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता जैसे विषयों पर ठोस पहल की। इस अध्यक्षता के माध्यम से भारत ने यह प्रदर्शित किया कि विकासशील देश भी वैश्विक नीतिनिर्माण में निर्णायक नेतृत्व दे सकते हैं। भारत की अध्यक्षता ने जहाँ देश की कूटनीतिक स्थिति को मज़बूती दी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक शांति के नए आयाम भी स्थापित किए।
मुख्य शब्द– भारत, जी–20 अध्यक्षता, वसुधैव कुटुम्बकम्, वैश्विक दक्षिण, सतत विकास, हरित ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुपक्षीय सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक शासन।

Introduction

01 दिसंबर 2022 को, भारत ने विश्व शक्तियों के सबसे प्रभावशाली समूह में से एक G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की। यह एक संयोग ही रहा कि उस समय भारत में न केवल G-20 की अध्यक्षता ग्रहण की बल्कि विश्व के सर्वशक्तिमान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी दिसंबर में ग्रहण की। यही नहीं बल्कि भारत सितंबर 2023 तक विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रीय मंच, शंघाई सहयोग संगठन की भी अध्यक्षता कर रहा है। भारतीय दृष्टिकोण से यह उपलबिध महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली है। वार्ताओं द्वारा वैश्विक आर्थिक एजेंडे को आकार देने और कई अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर अपने नेतृत्व के माध्यम से पहल करने का प्रयास किया।[1]

G-20 क्या है– G-20 , जिसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ ट्वेंटी है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और आपसी समझ का एक अन्तर सरकारी मंच है जिसमें विश्व के प्रमुख विकसित एवं विकासशील देश शामिल हैं। G-20 विश्व के अर्थव्यवस्था में ढांचागत सुधार करने, मौद्रिक संकटो से निपटने तथा व्यापार विस्तार एंव सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर वैश्विक संरचना और संचालन को कार्य रूप देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।[2]

G-20 की उत्पत्ति और विकास– देखा जाए तो मुख्य रूप से G-20 का जन्म आर्थिक समस्याओं के समाधान का परिणाम है। 1973 के पहले अरब, इजरायल युद्ध के कारण तेल संकट उत्पन्न हुआ जिसमें अमेरिका ने औद्योगिक देश के लिए एक मंच की अवधारणा दिया। इस तरह का विचार तब के अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जॉर्ज शुल्ज ने दिया था जिसमें उन्होंने वाशिंगटन डीसी में पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम के वित मंत्रियों की एक औपचारिक बैठक की। पुनःशुल्ज ने 1973 के मध्य में जब विश्व बैंक और आईएमएफ की एक बैठक हो रही थी जापान को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र इटली इसमें शामिल हुआ और पहली बार 1975 में G-6 बैठक फ्रांस में हुई। इसके पश्चात 1976 में प्रमुख विकसित

औद्योगिक राष्ट्र कनाडा को इसमें शामिल किया गया और इस प्रकार यह G-7 बना। 1994 के G-7 बैठक के समय यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने रसिया को एक अतिथि देश के रूप में इसमें शामिल किया। 1997 तक अतिथि देश के रूप में रहा और 1998 में औपचारिक रूप से G-7 का आठवां सदस्य बना और G-8 या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कहा जाने लगा। हालांकि वर्ष 2014 में यूक्रेन पर आक्रमण के कारण G-20 से बाहर कर दिया गया और पुनः इसे G-7 कहा जाने लगा।[3]

G-20 की औपचारिक स्थापना वर्ष 1999 में, एशिया में हुए वित्तिय संकट के बाद, G-7 देशों के वित मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा, वैश्विक आर्थिक और वित्तिय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। भारत G-20 का सदस्य 1999 में संस्थापक देश के रूप में बना। वर्ष 2007 में जब वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट पैदा हुआ जिससे विश्व के सभी देश प्रभावित हुए, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने G-20 को विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन का दर्जा दिया और इसके कार्य सूची का आधार बढ़ाते हुए इसमें भू–आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को भी शामिल कर लिया। वर्ष 2008 में G-20 को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच का नाम दिया गया और यह आर्थिक सहयोग और आपसी समझ एवं समर्थन के लिए वास्तव में एक वैश्विक मंच बन गया। शुरूवात में G-20 ने बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया लेकिन इसके बाद से इसने व्यापार, जलवायू परिवर्तन शयन सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार निवारण सहित अन्य मुद्दों के लिए अपने एजेण्डे का विस्तार किया। भारत दुनिया को पांचवी भारत की अध्यक्षता में 2023 में हुए दिल्ली शिखर सम्मेलन हमारे ग्रह के अस्तित्व के लिए खतरा बने परिस्थितिकी के संकट हल करने का एक मंच मुहैया कराया है। नवंबर 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (COP-27) और मॉन्ट्रियल में जैव विविधता सम्मेलन (COP-27) के नतीजे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के क्षति से जुड़ा वैश्विक परिस्थितिकी संकट को सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले नहीं रहे।

इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया कि समुंद्र हमारी जरूरत की 50 % ऑक्सीजन उत्पन्न करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड के पूरे उत्सर्जन का 25 % हिस्सा अवशोषित करता है और उत्सर्जन की वजह से उत्पन्न होने वाली गर्मी का 90 % अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार समुंद्र न केवल ग्रह का फेफड़ा बल्कि सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को घटाने वाला एक महत्वपूर्ण बफर है। उपर्युक्त के आलोक में भारत ऐसी भूमिका में स्वयं में पहल भी कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय सौर समझौता (इंटर सोलर अलायंस) आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (कोलिएशन ऑफ डिजास्टर रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर) लाइफ मूवमेंट आदि में शामिल है। भारत ने 2030 तक जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन 500 गीगावॉट रखने का लक्ष्य रखा है। इससे 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन का एक अरब टन कम हो सकेगा। वहीं 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी (बिजली बनाने में कार्बन डाई ऑक्साइड की दर) 45 प्रतिशत से भी कम हो जाएगी। साथ ही 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य अर्थात कार्बन उत्सर्जन में स्थिरता का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टनेबल डेवलपमेंट (IISD) के G-20 समूह से संबधित अनुसंधान के अनुसार 2014–2016 के दौरान जीवाश्म ईंधन के प्रति भारत सरकार के समर्थन में तीन प्रतिशत की कमी आई है। इसी प्रकार 2010–16 के दौरान कोयले के उत्पादन शुल्क तीन गुना हो गया है। कोयले पर निर्भरता के बावजूद भारत ने 2005 से 2016 की अवधि में अपने सकल राष्ट्रीय

उत्पाद (जीडीपी) में कार्बन का प्रभाव 24 प्रतिशत कम किया है। गलॉसगो में (2021) हुए 26 वे पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन (COP-26) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी ने पंचामृत रणनीति की घोषणा की जिसमें ऊर्जा के स्त्रोतों को अपनाने का विशेष उल्लेख किया। भारत विकासशील देशों के समान दृष्टिकोण वाले देशों के समूह (लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्री) के अग्रणी देश के नाते भारत तथा अन्य देशों के समानता पर जोर देता है और यह मांग करता है कि विकासशील देशों पर ऐसे पदार्थों के उपयोग न करने पर दबाव ना डालें जो उसके विकास पथ से विमुख कर दे। भारत इसके साथ इस दृष्टिकोण का भी समर्थक है कि विश्व में न्याय पूर्ण तरीके से प्रदूषण मुक्त अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अपनाए जाने के लिए वैश्विक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों द्वारा वित्तीय मदद तथा सहयोग दिए जाने की अनदेखी नहीं की जा सकती।[4]

खाद्य सुरक्षा– वैश्विक खाद्य कीमतें ऊंची बनी हुई। इसका मुख्य कारण रूस, यूक्रेन युद्ध से है क्योंकि दोनों बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं। इन दोनों देशों के युद्ध में उलझे होने के कारण गेहूं के जहाज पर लदाई में खलल पड़ा है। इसलिए भारत दुनिया भर में मोटे अनाज (मिलेट्स) के पैदावार में नई जान फूंकने पर जोर दे रहा है। आज करीब 130 देश में मोटे अनाज उगते हैं जिसमें भारत सबसे बड़ा है। 2019 में दुनिया भर में कुल 8.9 करोड़ टन मोटे अनाज उगाए गए जिनमें भारत का योगदान बीस प्रतिशत है। इसके मुकाबले गेहूं की वैश्विक उपज इस साल 80 करोड़ टन थी। भारत में पिछले साल संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने की अगुवाई की जिसे 72 देशों को समर्थन से पारित किया गया। भारत की G-20 के दिल्ली शिखर सम्मेलन में मोटे अनाजों के तरफ जाने के लिए सदस्य देशों पर जोर डाला जिसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी क्योंकि गेहूं से इसके कार्बन उत्सर्जन और पानी की खपत कम है।[5]

डिजिटल फासले को पाटना– एक और क्षेत्र है जहां भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है यह है डिजिटल फासले को पाटना। तकरीबन चार अरब लोगों या दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। करोड़ो ऐसे हैं जो बैंक से नहीं जुड़े हैं। इसके अलावा दुनिया के 195 में से 130 से ज्यादा देशों के पास अभी डिजिटल भुगतान प्रणाली नहीं है। भारत अपना खुद उदाहरण सामने रखकर समावेशी डिजिटल क्रांति लाने की अगवाई कर रहा है। अपनी जेएम (JAM), जनधन बैंक खाता, आधर कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से सरकार जन कल्याण योजनओं के तहत नगद सहायता के लिए शायद दुनिया के सबसे बड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अंजाम दे पा रहा है। सरकार ने 44 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाता खोले सार्वजनिक क्षेत्र के यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के जरिए पिछले साल (2022) में 46.8 अरब लेनदेन किए गए जो दुनिया के रियल टाइम लेनदेन का 40% हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारत ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है।

समावेशी वैश्विक स्वास्थ्य- G-20 वैश्विक स्वास्थ्य में सहयोग प्रदान करने और एकत्रित करवाई की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न बहुपक्षीय भागीदार के बीच चर्चाओं के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करती है। G-20 की अध्यक्षता में पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, तैयारी की और प्रतिक्रिया (एक स्वास्थ्य और रोगाणुरोधी प्रतिरोध) जिसके अंतर्गत बेसिक स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से रोकथाम तैयारी और भविष्य की महा मारियों का प्रबधंन करना। इसके लिए जरूरी

है कि एक स्वास्थ्य ढांचे के अंतर्गत एएमआर से (एन्टी माइक्रोवियल रेसिस्टेंट) निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिए जाने की जरूरत है। हमारा मुख्य जोर सुरक्षित और प्रभावी रोगाणु रोधी के निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्सहान देने के साथ G-20 में फोक्स क्षेत्रों में से मनुष्य और जानवरों दोनों में से रोगाणु रोधी के दुरूपयोग को कम करना है।

चिकित्सा प्रत्युपाय (वैक्सीन चिकित्सा और निदान) की पहुंच और उपलब्धता दूसरी प्राथमिकता है। भारत अपनी और 120 से अधिक देशों की स्वास्थ्य सबंधी जरूरत को पूरा करके कॉविड–19 संकट के दौरान वैश्विक फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में ताकत का प्रदर्शन किया है। हमने स्वदेशी कोविड–19 के टीके विकसित किए और 2.19 से अधिक टीकों को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य किया। भारत की अध्यक्षता में G-20 देशों की गुणवत्ता और प्रभावी चिकित्सा प्रत्युपाय की उपलब्धता, पहुंच और समर्थ में अंतर को दूर करने के लिए स्थाई तंत्र और प्रभावी साझेदारी पर विचार विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया है। और क्षेत्र जहां भारत G-20 की अध्यक्षता के समय अपने डिजिटल स्वास्थ्य के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने प्रयासों को साझा कर रहा है। कोविड–19 प्राथमिक स्वास्थ्य की बढ़ती मांग को जन्म दिया है जो टेलीमेडिसिन निगरानी और दूरस्थ नैदानिक प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं में अत्याधुनिक तकनीकी को बेहतर ढंग से शामिल करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। टेलीमेडिसिन परामर्श के लिए भारत के ई संजीवनी प्लेटफार्म ने हाल ही में आठ करोड़ से अधिक परामर्श को प्रदान कर उल्लेखनीय मिल का पत्थर प्राप्त किया है जिससे सदस्य देशों को परिचित कराया जा सकता है।

वैश्विक कौशल और सामाजिक सुरक्षा– G-20 देशों ने सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोजगार के महत्व को पहचाना है। इसके लिए उन्होंने रोजगार कार्य बल का गठन किया। इस कार्य बल को प्रारंभ में एक वर्ष के लिए बनाया गया लेकिन इसके महत्व को देखते हुए G-20 देशों ने 2014 में इसे रोजगार कार्य समूह (ईडब्लूजी) में बदलने का फैसला किया। इस समूह का उद्देश्य श्रम रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए टिकाऊ, संतुलित समावेशी विकास और रोजगार के सेवाओं को बढ़वा देना है। ऐसा G-20 सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सामाजिक भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर किया जाता है। समूह की वार्षिक अनुसूची श्रम और रोजगार मंत्रियों की घोषणा के अनुसार G-20 अध्यक्ष देश द्वारा बनाई जाती है। विभिन्न देशों की अध्यक्षता के दौरान हुए कामों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रोजगार कार्य समूह एक बहू–वर्षीय एजेंडे के तहत कार्य करता है जिसे इसके सदस्य विकसित करते हैं। एजेंडे को वार्षिक तौर पर मूल्यांकित और जरूरत के मुताबिक नवीनीकृत भी किया जाता है। रोजगार कार्य समूह निश्चित करता है कि उन विषयों पर प्रगति हुई हो जिन पर लंबे समय से कार्य किया जा रहा है।[6]

रोजगार कार्य समूह जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है उनमें से एक है– सामाजिक सुरक्षा, जो यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से अहम है कि श्रमिकों को उनके समूचे कामकाजी जीवन में पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। सामाजिक सुरक्षा में बेरोजगारी से निपटने के लिए दिए जाने वाला लाभ, पेंशन, और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई अहम कार्य होते हैं। रोजगार कार्य समूह यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रणाली प्रभावी, कुशल और सभी के लिए सुलभ हो। इसके साथ ही भारत का उद्देश्य रोजगार एवं इससे सबंधित मुद्दों पर वैश्विक चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान देना है। साथ ही ऐसा सार्थक समाधान भी प्रस्तुत करना है जो

दुनिया भर के कर्मचारियों और नौकरी देने वाले भी लाभान्वित हो। अब तक के G-20 की बैठक में रोजगार कार्य समूह ने तीन प्राथमिकताओं को चिन्हित किया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है–

1. विभिन्न देशों में कौशल के स्तर पर कार्य असमानताएं मौजूद है जिसकी खाई को पाटना आवश्यक है।
2. सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण ताकि सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को लंबी अवधि तक वित्तीय रूप से टिकाऊ रखा जा सके।
3. गिग और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था के दौर में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल देना। गिग अर्थव्यवस्था एक ऐसा श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थाई कर्मचारियों के बजाय अस्थाई और अंशकालिक तौर पर लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। यह वह प्लेटफार्म है जिसमें डिजिटल प्लेटफार्म या ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए अस्थाई स्वतंत्र या अनुबंधित कार्य की सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। जैसे आने–जाने की सुविधा के लिए गाड़ी मुहैया कराना,घर तक खाना पहुंचाना, किराए के लिए घर दिलाना, कोचिंग, अनुवाद, रिपेयरिंग आदि जैसी कई सेवाएं प्रदान करना है। इन्होंने व्यक्तियों और व्यवसाय के लिए नए एवसर पैदा किए हैं। इस नई प्रणालियों की सुरक्षा, कर्मचाारियों को मिलने वाले लाभ और उनके शोषण को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। इस को समझते हुए ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो कर्मचारी के स्थाई समाधान बन सके।

<u>महिलाओं के नेतृत्व में विकास</u>– W-20 को आधिकारिक तौर पर 2015 में G-20 की तुर्किए के अध्यक्षता के तहत स्त्री पुरूष समानता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्त्री पुरूष समानता के मुद्दे की चर्चा मुख्यधारा में शामिल हो और G-20 नेताओं के घोषणाओं में उन नीतियों और प्रतिबद्धताओं के रूप में शामिल किया जाए जो लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान यह कर रहा है और उसने पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र को फोकस किया है– 1 उधमिता में महिलाएं, 2 जमीनी स्तर पर महिलाएं, 3 स्त्री पुरूष समानता. 4 शिक्षा और कौशल, 5 महिला तथा लड़कियों जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चेंजमेकर के रूप में। इसके अतिरिक्त जमीनी स्तर पर महिला नेताओं के लिए सक्षम परिस्थितिक तंत्र बनाना, सार्वजनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में लड़कियों की समान भागीदारी, जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटना, प्रोधोगिकी का लाभ देना, नैनो, माइक्रो और स्टार्टअप इंटरप्राइजेज में महिलाओं को सशक्त बनाना आदि अन्य उद्देश्य है।

<u>स्टार्टअप से उद्यमिता को बढ़ावा-</u> दुनिया भर में स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल में G-20 ने स्टार्टअपस (स्टार्टअप्स 20) के लिए एक नया व्यवसाय समूह गठित किया है। यह नवीन विचार भारत ने पेश किया है। स्टार्टअप व्यवसाय समूह में G-20 देशों को बदलने और नवाचार, सहयोगात्मक प्रयास, उद्यमशीलता की भावना और समावेश के माध्यम से विकास की प्रवृति आगे बढ़ाने की क्षमता है। स्टार्टअप व्यवसाय समूह के माध्यम से साझेदारी करके सदस्य देशों के स्टार्टअप नए उत्पादों या सेवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण मुद्दों को पहचानने और निपटने में सक्षम है जो न केवल व्यवसाय रखते हैं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं से भी दूर करते हैं।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसमें वर्तमान में लगभग 93000 स्टार्टअप शामिल है, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने देश के जीडीपी में 4 से 5 प्रतिशत योगदान करने की क्षमता है। नैस्कॉम के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 08, August 2025

2025 तक 12.5 लाख से अधिक रोजगार सृजन की क्षमता रखता है। साथ ही स्टार्टअप अपनी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता कुल नौकरियों की संख्या 2020 से 2025 तक 39 लाख करने की क्षमता रखता है। भारतीय युवा आबादी वैश्विक नेतृत्व के लिए देश की आकांक्षाओं में योगदान कर रहा है। स्टार्टअप 20 व्यवसाय समूह स्टार्टअप के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने और विस्तार करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।[7]

Reference: -

(1) What are the criteria for G-20 Membership? Archived 2013-05-06 at the os cSad e"khu from the official G-20 website.
(2) G-20 finance Ministers committee to sustainable development interpress service 2015-09-09 अभियान तिथि 2023-09-14.
(3) G-20 members A G-20 2014 web. Archive org 2014-02-03 मूल से पुरालेखित 3 फरवरी 2014 अभिगमन तिथि 2023–04–2014.
(4) G-20 insights Homepage,"Global Solutions initiativeA Global Solution summit (अंग्रेजी में) अभिगमन तिथि 2023–09–2014.
(5) "WTO State" world trade org anisalion. अभिगमन तिथि 2023-04-15.
(6) Report of Selected countries and subjeets: April 2023. Imf. Org. International Monetary fund.
(7) World economic dutlook database: WEO Groups and aggregate information. International Monetary fund April 2017– अभिगमन तिथि 10-04-2024